



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राजशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, बुधवार, 27 सितम्बर, 1995/ 5 अक्टूबर, 1917

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला, 27 सितम्बर, 1995

संख्या 1-37/95-वि० ए०.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रकृति एवं कार्य संवधान विधायकी, 1973 के नियम 135 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संवर्धन) वि० ए०, 1995 (1995 में विद्यमान)

3017-राजपत्र/95-27-9-95 -1,231.

(3895)

पृष्ठ 1 का पृष्ठ 1

उत्तर

समाधारण शासन, विभाजन प्रश्न, २७ मिनट, 1000/10 भाषित, 1017

शिकायत (1) को शिकायत प्रती (1000/10) को विभाजन प्रश्न विभाजन प्रश्न में पर स्थिति को गया है, समाधारण को शिकायत समाधारण शासन में भविष्य करने हेतु वैधित किया गया है।

हस्ताक्षर/
मिनि

हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधायक, १९९३

(विधान सभा में सभा पुर स्थापित)

हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, १९९४ (१९९४ का १२) का संशोधन करने के लिए विधायक ।

भारत गणराज्य के किंगडोमीयन वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित है।

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, १९९३ है । संक्षिप्त नाम और धारा १।

(२) यह प्रथम अधिवेशन, १९९३ में पठित हुआ समाप्ति पाया ।

२. हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, १९९४ (जिस द्वारा इसके पञ्चायत में अधिनियम बना गया है) की धारा १.३ के पञ्चायत निम्नलिखित धारा १.३ के और १.३ के अंतर्गत स्थापित की जायेगी, यथाः

धारा १.३ का और १.३ के अंतर्गत स्थापित ।

"१.३ के निम्नलिखित धारों का लब्ध और उनकी अधिकतम शक्ति (१) निम्नलिखित में है कि अधिनियम निम्नलिखित अधिनियम के अधिनियम का जो, जिस तारीख को, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित किया गया है और जिस निम्नलिखित परिणामों की घोषणा की तारीख को, जिसके अंतर्गत में दोनों तारीख आती है, बीच स्वयं द्वारा या इसके निम्नलिखित अधिनियम द्वारा प्रमाण या अधिकृत किया गया है, पुराने और शब्दों लब्ध या तो वह स्वयं स्वयं या अधिनियम निम्नलिखित अधिनियम द्वारा स्थापित ।

(२) लब्ध में पूर्ण विधिनिष्ठा अन्तर्गत हीमो जैसी राज्य सरकार द्वारा राज्य निम्नलिखित अधिनियम के अधिनियम । निम्नलिखित की जाये ।

(३) जहाँ स्वयं का जो कि स्वयं स्वयं अधिकतम हीमो जो राज्य निम्नलिखित अधिनियम के अधिनियम में राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित की जाये ।

१.३ के लब्ध का अधिकतम किया जाये निम्नलिखित में है कि निम्नलिखित लब्ध लब्ध अधिनियम निम्नलिखित अधिनियम के निम्नलिखित की तारीख से या अधिक निम्नलिखित में लब्ध में अधिक निम्नलिखित अधिनियम है, और जहाँ निम्नलिखित की तारीख निम्नलिखित में कि जहाँ तारीखों में से पञ्चायत तारीख से तीस दिन के अन्तर अपने निम्नलिखित अधिनियम में लब्ध जो स्वयं लब्ध की शब्दों पति हीमो निम्नलिखित में कि जहाँ निम्नलिखित अधिनियम में धारा १.३ के अधिनियम स्थापित है, राज्य निम्नलिखित अधिनियम द्वारा यथा निम्नलिखित अधिकारी के पास अधिकतम करण ।"

धारा 21 3. मूल अधिनियम की धारा 21 में, उप-धारा (5) के पश्चात् निम्नलिखित उप-
का संशोधन। धारा (5-क) जोड़ी जाएगी, अर्थात् :—

“(5-क) धारा 13-क के उल्लंघन में व्यय उपगत या प्राधिकृत करना।”।

1995 के 4. (1) हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) अध्यादेश, 1995 का एतद्द्वारा
अध्यादेश निरसन किया जाता है।

संख्यांक 1 (2) हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) अध्यादेश, 1995 के निरसित होते
का निरसन। हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के
तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जाएगी।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

इस समय, हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का 12) में निर्वाचन-व्यय की, जो नगर निगम का निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी द्वारा उपगत किया जा सकेगा, धनीय सीमा नियत करने और राज्य निर्वाचन आयोग को निर्वाचन व्ययों का लेखा प्रस्तुत करने के लिए, कोई उपबन्ध नहीं है। नगर निगम के लिए स्वतन्त्र और निष्पक्ष निर्वाचन सुनिश्चित करने के लिए, नगर निगम का निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी द्वारा उपगत किए जाने वाले निर्वाचन व्यय की धनीय सीमा नियत करना और राज्य निर्वाचन आयोग को निर्वाचन-व्यय की धिवरणी प्रस्तुत किए जाने को बाध्यकर बनाना बांछनीय है। नगर निगम में पार्षदों के प्रतिपक्ष स्थानों के लिए निम्न भविष्य में उप-चुनाव करवाए जाने हैं, इसलिए, पूर्वोक्त अधिनियम में तत्काल संशोधन करना आवश्यक हो गया है।

क्योंकि हिमाचल प्रदेश विधान सभा सत्र में नहीं थी और हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का 12) में तत्काल संशोधन दिया जाना अपेक्षित था, अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल द्वारा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) के अर्थात् हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) अध्यादेश, 1995 (1995 का 1), 29 जुलाई, 1995 को प्रख्यापित किया गया और इसे प्रथम अगस्त, 1995 के राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण) में प्रकाशित किया गया था। उक्त अध्यादेश अब नियमित अधिनियमिनि द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना अपेक्षित है।

अतः यह विधेयक, उपरोक्त अध्यादेश को बिना किसी उपान्तरण के प्रतिस्थापित करने के लिए है।

जय बिहारी लाल खाची,
प्रभारी मन्त्री।

शिमला :

27 सितम्बर, 1995.

बिस्तीय जापन

-शून्य-

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी जापन

विधेयक का खण्ड 2 राज्य सरकार को, राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से निर्वाचन में के हर अभ्यर्थी द्वारा लेखे में अन्तर्विष्ट की जाने वाली विशिष्टियां और उपगत किए जाने वाले व्यय के सम्बन्ध में नियम बनाने के लिए सशक्त करेगा। प्रस्तावित प्रत्यायोजित आवश्यक और सामान्य स्वरूप का है।

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 9 of 1995.

THE HIMACHAL PRADESH MUNICIPAL CORPORATION
(AMENDMENT) BILL, 1995

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

*to amend the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994
(Act No. 12 of 1994)*

Be it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Forty-sixth Year of the Republic of India as follows:—

Short title
and commence-
ment.

1. (1) This Act may be called the Himachal Pradesh Municipal Corporation (Amendment) Act, 1995.

(2) It shall and shall be deemed to have come into force on 1st day of August, 1995.

Insertion of
sections 13 A
and 13 B.

2. After section 13 of the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994 (hereinafter called the principal Act), the following sections 12 of 1994.

“13 A. Account of election expenses and maximum thereof.—

(1) Every candidate at an election shall, either by himself or by his election agent, keep a separate and correct account of all expenditure in connection with the election incurred or authorised by him or by his election agent between the date on which he has been nominated and the date of declaration of the result thereof, both dates inclusive.

(2) The account shall contain such particulars, as may be prescribed by the State Government in consultation with the State Election Commission.

(3) The total of the said expenditure shall not exceed such amount as may be prescribed by the State Government in consultation with the State Election Commission.

13 B. Lodging of account.—Every contesting candidate at an election shall, within thirty days from the date of election of the returned candidate or, if there are more than one returned candidates at the election and the dates of their election are different, the later of those two dates, lodge with the officer, as may be appointed by the State Election Commission, an account of his election expenses which shall be a true copy of the account kept by him or by his election agent under section 13A.”

3. In section 21 of the principal Act, after sub-section (5), the following sub-section (5A) shall be added, namely : --

Amendment of section 21.

“(5A) the incurring, or authorising, of expenditure in contravention of section 13A.”

4. (1) The Himachal Pradesh Municipal Corporation (Amendment) Ordinance, 1995, is hereby repealed.

Repeal of Ordinance No. 1 of 1995.

(2) Notwithstanding the repeal of the Himachal Pradesh Municipal Corporation (Amendment) Ordinance, 1995, anything done or any action taken under the said Ordinance, shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

At present there is no provision in the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994 (Act No. 12 of 1994) to fix a monetary limit of election expenses which can be incurred by a candidate contesting the election to the Municipal Corporation and to submit an account of election expenses to the State Election Commission. In order to ensure free and fair elections to the Municipal Corporation it is desirable to fix a monetary limit of election expenses to be incurred by a candidate contesting the elections to the Municipal Corporation and to make the condition of submission of election expenses return to the State Election Commission obligatory. The bye-election to certain seats of Councillors in the Municipal Corporation are to be held in the near future, as such it has become necessary to make immediate amendments in the aforesaid Act.

Since the Himachal Pradesh Legislative Assembly was not in session and the aforesaid amendments in the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994 (Act No. 12 of 1994) was required to be made urgently, the Governor, Himachal Pradesh, promulgated under Clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, the Himachal Pradesh Municipal Corporation (Amendment) Ordinance, 1995 (Ordinance No. 1 of 1995) on the 29th July, 1995 and the same was published in the Rajpatra, Himachal Pradesh (Extra-ordinary), dated the 1st August, 1995. The said Ordinance is now required to be replaced by a regular enactment.

Hence this Bill seeks to replace aforesaid Ordinance without any modification.

JAI BIHARI LAL KHACHI,
Minister-in-Charge.

SHIMLA:

The 27th September, 1995.

FINANCIAL MEMORANDUM

—NIL—

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Clause 2 of the Bill empowers the State Government to make rules, in consultation with the State Election Commission, regarding particulars as may be contained in the account and maximum expenditure to be incurred by each candidate at an election. The proposed delegations are essential and normal in character.